अब पीएनजी कनेक्शन के लिए टारगेट

आवेदन और कनेक्शन की लगातार होगी मॉनीटरिंग

संकट के बीच एलपीजी के विकल्प पर दिया जोर

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 4 अप्रैल. राज्य सरकार किल्लत के बीच अब सीएनजी के विकल्पों पर जोर दे रही है. लिहाजा अब प्रदेश में पीएनजी कनेक्शन के लिए नए टारगेट दिए जा रहे हैं.

शनिवार को अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी ने सीजीडी संस्थाओं, ऑयल कम्पनी एवं जिला आपूर्ति अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) संस्थाएं अगले 3 माह में दिये जाने वाले पीएनजी कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित करें. साथ ही सीजीडी संस्थाओं द्वारा प्रतिदिन किये जा रहे आवेदन एवं उसके विरुद्ध दिये जा रहे पीएनजी कनेक्शन की सतत मॉनीटरिंग की जाये. एसीएस श्रीमती शमी ने सीजीडी संस्थाओं को पीएनजी के लाभ एवं पीएनजी कनेक्शन की प्रक्रिया से संबंधित एफएक्यू तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश नोडल सीजीडी संस्था थिंक गैस को दिये. भारत सरकार के गतिशक्ति पोर्टल पर सीजीडी संस्थाओं को पाइप-लाइन अपलोड करने के निर्देश दिये गये. सीजीडी संस्थाएं जिलेवार एवं लोकेलिटीवाइज कैम्प शेड्यूल कर जिला प्रशासन एवं विभाग को उपलब्ध करायें. शहर के जिन स्थानों में पाइप-लाइन गई है, उसके आस-पास के क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को ऑयल कम्पनी द्वारा अवगत कराया गया है कि वह पीएनजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिये तत्काल आवेदन करें. इसके बाद पीएनजी कनेक्शन प्राप्त न करने की स्थिति में आगामी 3 माह में एलपीजी का कनेक्शन बंद किया जा सकता है. जिला आपूर्ति अधिकारियों को एमपीआईडीसी के जिला अधिकारी, जिले में स्थित पॉलीटेक्निक तथा आईटीआई से प्रशिक्षणार्थियों की सूची सीजीडी संस्था को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये. सीजीडी संस्था द्वारा इन प्रशिक्षणार्थियों को वर्तमान वेण्डर के साथ क्लब कर मैन पॉवर बढ़ाया जाएगा. एसीएस श्रीमती शमी ने कहा कि एलपीजी बुकिंग करने के बाद कितने दिन में डिलेवरी होगी, इस संबंध में उपभोक्ताओं को एसएमएस भेजना सुनिश्चित करें. प्रदेश में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है.

> **पीएनजी कनेक्शन विस्तार पर जोर**
>
> सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में प्रदेश में कार्यरत 10 संस्थाओं को पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जहां घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं की मांग और शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है. पीएनजी पाइप लाइन जिन क्षेत्रों में बिछ चुकी है, वहां आवासीय परिसर, स्कूल, हॉस्टल, कॉलेज, कम्युनिटी किचन और आंगनवाड़ी केंद्रों को आवेदन प्राप्त होने के 5 दिन में पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.

मंत्रालय के गलियारे से

कन्हैया लोधी

विभाग बदला, फिर भी मनमानी नहीं रुकी

प्रदेश के एक ताकतवर अफसर का कुछ समय पहले विभाग बदल दिया गया था. जिस विभाग को बदला गया, वहां के ताकतवर कॉडर के साथ साहब तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे, इसे लेकर लगातार शिकवा- शिकायत का दौर चल रहा था.

यहां तक कि विभाग के मुखिया कई मामलों में स्वयं को असहाय महसूस करते थे, आखिरकार पूरे कॉडर की मुहिम रंग लाई और उन्हें विभाग से रूखसत होना पड़ा, लेकिन दूसरी जगह पहुंचने के बाद भी लगता है साहब के मिजाज में कोई बदलाव नहीं आया, साहब के साथ एक विभाग पिछले कार्यकाल में भी चिपका हुआ था और इस बार भी चिपका रह गया है, अब इसी विभाग से जुड़े एक ताकतवर संवैधानिक संस्था के फरमान को साहब ने धता बता दिया है और साफ इंकार कर दिया है. इससे अब अघोषित द्वंद की स्थिति बन गई है. साहब का मिजाज तो मिजाज ही है, विभाग बदल गया, लेकिन मनमानी नहीं रूक रही है.

क्या अब भाग्योदय का समय आ गया

पिछले विधानसभा चुनाव में खेत रहे एक ताकतवर नेता के लगता है कि अब भाग्योदय का समय आ गया है. अब सब कुछ उनके पक्ष में होता दिख रहा है. परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि एक बार फिर विधानसभा की राह उनके लिए खुल सकती है. पिछले कार्यकाल तक सरकार की आंख, कान, नाक रहे ये नेताजी लंबे समय से गर्दिश में रहे, अब ताजा जानकारी के मुताबिक उपचुनाव की तैयारियों में लग गए हैं. यदि कोई और पेंच नहीं आया तो फिर उनके क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है. अब देखना ये है कि आधी बाजी तो उन्होंने मार ली है, तो क्या पूरी भी मार पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा.

फजीहत कराने का आइडिया दिया किसने

पिछले दिनों कांग्रेस के प्रदेश मुखिया ने अति आत्मविश्वास दिखाया, जिसका खामियाजा उन्हें तुरंत ही भुगतना पड़ गया. दरअसल नेता अपने आस-पास बने बबल में ऐसे घिरे रहते हैं, कि उन्हें जमीनी सच्चाई की ज्यादा भनक नहीं होती. लिहाजा साहब ने भी रेंडमली अपने नेतृत्व का रेफरेंडम करा लिया, उन्हें भरोसा था कि सब एक सुर में उनके लिए कसीदें पढ़ेंगे, लेकिन ये दांव उलटा पड़ गया. उनके निर्णयों को भी खुले में चुनौती मिल गई. बस फिर क्या था, जितना रायता उन्होंने फैलाया, बाकी वक्त उन्होंने इसे समेटने में ही लगा दिया. अब लोग ये तलाशने में लगे हैं कि आखिर उन्हें अपनी फजीहत कराने का आइडिया दिया किसने था.

संगठन पर सरकार का असर

लगता है कि भाजपा संगठन पर अब सरकार का असर होने लगा है. अब तक तो प्रशासनिक तबादले ही देर रात को होते थे, लेकिन अब राजनीतिक नियुक्तियां भी देर रात होने लगी है. पिछले दिनों भाजयुमो की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हुई. ये सूची दिन में भी किसी समय जारी हो सकती थी, यदि देर रात को सूची को अंतिम रूप दिया गया तो भी अगले दिन तक का इंतजार किया जा सकता था, लेकिन सूची मध्य रात्रि को जारी की गई. यानी अब प्रशासन के साथ राजनीति में भी चौंकाने वाले निर्णय कभी भी किसी भी समय हो सकते हैं, भले ही देर रात क्यों न हो?

प्रदेश में 4 मौसम सिस्टम सक्रिय

45 जिलों में आंधी-बारिश व ओलावृष्टि का अलर्ट

भोपाल, 04 मार्च. मध्य प्रदेश में इस समय मौसम ने अचानक करवट ले ली है. एक साथ चार अलग-अलग मौसम सिस्टम सक्रिय होने के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है.

मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति 7 अप्रैल तक बनी रह सकती है, जिससे लोगों और किसानों दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है. दरअसल, प्रदेश में दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवाती परिसंचरण) और दो टर्फ लाइन सक्रिय हैं. एक टर्फ लाइन प्रदेश के बीचोंबीच गुजर रही है, जबकि दूसरी ऊपरी स्तर पर बनी हुई है. इसके साथ ही पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में चक्रवाती गतिविधियां भी जारी हैं. इन सभी सिस्टम के संयुक्त प्रभाव से पिछले कुछ दिनों से मौसम लगातार अस्थिर बना हुआ है और कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिर रहे हैं. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए लगभग 45 जिलों में अलर्ट जारी किया है. इनमें भोपाल, ग्वालियर समेत कई बड़े जिले शामिल हैं.

> जबलपुर, कटनी, छतरपुर, पन्ना और दमोह में ओलावृष्टि की विशेष चेतावनी दी गई है. इसके अलावा प्रदेश के कई अन्य जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. हवा की रफ्तार भी काफी तेज रहने की आशंका है. कुछ क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आंधी चल सकती है, जबकि अन्य स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. इस कारण पेड़ गिरने, बिजली बाधित होने और फसलों को नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है. 7 अप्रैल के बाद एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होगा, जिससे 10 अप्रैल तक हल्की मौसम गतिविधियां जारी रह सकती हैं. इसके बाद जैसे ही मौसम साफ होगा, तापमान तेजी से बढ़ेगा.

फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर संविदा अधिकारी बर्खास्त

सिवनी, 04 अप्रैल. जिले की जिला पंचायत में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए परियोजना अर्थशास्त्री (संविदा) वंदना मुड़िया की सेवाएं 16 वर्षों बाद समाप्त कर दी गई हैं.

आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंजली शाह द्वारा की गई है. मामले में संबंधित के खिलाफ डूंडासिवनी थाना में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में पुलिस ने आवेदन वापस कर पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. यह मामला भोपाल स्थित लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज शिकायत के बाद उजागर हुआ.

जांच में सामने आया कि संबंधित अधिकारी ने अपनी वास्तविक जाति छिपाकर अनुसूचित जनजाति वर्ग के तहत नौकरी प्राप्त की, जबकि दस्तावेजों में उनकी जाति ढीमर (ओबीसी) दर्ज पाई गई. जिला स्तरीय जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद सेवा समाप्ति की कार्रवाई की गई है तथा आगे आपराधिक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है.

एनएसयूआई का पोस्टर प्रदर्शन

विशेष संवाददाता

भोपाल, 4 अप्रैल. भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने भोपाल में कथित फर्जी अस्पतालों के बढ़ते मामलों के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया.

संगठन ने पोस्टर अभियान चलाकर ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई, जो इन अवैध अस्पतालों को संरक्षण दे रहे हैं. एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने आरोप लगाया कि शहर में कई अस्पताल नियमों का उल्लंघन करते हुए कागजों में फर्जी तरीके से डॉक्टरों और स्टाफ का उल्लेख कर संचालित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि लगातार शिकायतों और विरोध के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है. प्रदर्शन के दौरान लगाए गए पोस्टरों में व्यंग्यात्मक संदेश लिखे गए, जैसे 'भोपाल में फर्जी अस्पताल खोलने के लिए संपर्क करें नट्टू शर्मा' और 'फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट के लिए संपर्क करें टीम नटवरलाल'.

सड़क दुर्घटना में ससुर-दामाद की मौत

मुरैना. जिले के जौरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार ससुर और दामाद की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस सूत्रों के अनुसार ग्राम सहसराम निवासी पीरू खान अपनी बेटी की शादी के कार्ड बांटकर अपने दामाद शाहिद के साथ बाइक से लौट रहे थे. इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. बताया गया कि हादसे में कार सवार एक व्यक्ति भी घायल हुआ है, जिसे जिला अस्पताल मुरैना से गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है. घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है.

डायल-112 कर्मियों की त्वरित कार्रवाई

घायल व्यक्ति को चिकित्सकीय सहायता कराई गई उपलब्ध

विशेष संवाददाता

इंदौर, 4 अप्रैल. जिले में डायल-112 कर्मियों की त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई से रात्रि गश्त के दौरान घायल अवस्था में मिले एक व्यक्ति को समय पर चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई गई.

यह घटना 4 अप्रैल को थाना तेजाजी नगर क्षेत्र के अंतर्गत केलोद फाटा के पास हुई. नियमित गश्त के दौरान एफआरवी स्टाफ ने सड़क किनारे एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल अवस्था में देखा. इसकी सूचना तुरंत राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-112, भोपाल को दी गई, जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई.

तत्परता दिखाते हुए आरक्षक मोहन मालवीय और आरक्षक आशीष पालीवाल तथा पायलट मोहित जाट ने घायल व्यक्ति को बिना किसी देरी के एफआरवी वाहन के माध्यम से एम.वाय. अस्पताल, इंदौर पहुंचाया. डायल-112 टीम की सतर्कता और मानवीय दृष्टिकोण के कारण घायल व्यक्ति को समय पर उपचार मिल सका.

यह घटना 'डायल-112 हीरोज' पहल के तहत मध्यप्रदेश पुलिस की आमजन की सुरक्षा, आपातकालीन सहायता और नागरिक सेवा के प्रति चौबीसों घंटे प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

आरपीएफ ने सुरक्षा और सहायता में रिकॉर्ड उपलब्धियां की हासिल

भोपाल, 4 अप्रैल. पश्चिम मध्य रेलवे ने भोपाल मंडल के अनुसार, वित्तीय वर्ष अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के दौरान रेल सुरक्षा बल ने यात्रियों और रेल संपत्ति की सुरक्षा में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कीं.

आरपीएफ ने चौबीसों घंटे सतर्क रहकर सुरक्षित माल परिवहन के साथ-साथ यात्रियों को सुरक्षा और सहायता प्रदान की. ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 720 बिछड़े, घर से भागे या अपहृत बच्चों को सुरक्षित उनके परिजनों या चाइल्ड लाइन को सौंपा गया. ऑपरेशन अमानत में 973 यात्रियों को लगभग 2.88 करोड़ मूल्य का खोया सामान वापस किया गया. ऑपरेशन जीवन रक्षा के अंतर्गत 33 लोगों की जान बचाई गई, जबकि ऑपरेशन मेरी सहेली के तहत प्रतिदिन औसतन 110 ट्रेनों में महिला यात्रियों को सहायता दी गई. रेल अधिनियम के तहत 53,566 मामलों में कार्रवाई कर ?3.81 करोड़ जुर्माना वसूला गया. ऑपरेशन उपलब्ध में 64 लोगों को गिरफ्तार कर 52 लाख से अधिक मूल्य के ई-टिकट जब्त किए गए. अनाधिकृत वेंडरों के खिलाफ 18,166 मामलों में कार्रवाई कर 2.20 करोड़ जुर्माना वसूला गया. रेल संपत्ति चोरी के 328 मामलों में 635 आरोपियों को गिरफ्तार कर संपत्ति बरामद की गई.

रेल मार्ग से भी आएंगे करोड़ों श्रद्धालु, स्टेशन पर जुटा रहे सुविधा

- चिंतामन स्टेशन कनेक्टिविटी मार्ग का तेजी से चल रहा काम
- सिंहस्थ से पहले उज्जैन का सड़क ढांचा होगा मजबूत
- सिंहस्थ मेला अधिकारी और कलेक्टर ने भी लिया जायजा

नवभारत न्यूज

उज्जैन. महाकाल की नगरी में महाकुंभ के दौरान 30 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन की जो तैयारी की जा रही है, उसमें करोड़ों श्रद्धालु रेल मार्ग से भी आएंगे, यही कारण है कि चिंतामण रेलवे स्टेशन पर भी सुविधाएं जुटाई जा रही है.

सिंहस्थ महापर्व 2028 की व्यापक तैयारियों के तहत शहर में चल रहे मार्ग निर्माण और मार्ग चौड़ीकरण कार्यों की प्रगति की जो फेहरिस्त बनाई गई है उसमें चिंतामण रेलवे स्टेशन का क्षेत्र भी शामिल कर लिया गया है. सिंहस्थ जैसे विशाल धार्मिक आयोजन को ध्यान में रखते हुए उज्जैन शहर में आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है. लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आगमन को ध्यान में रखते हुए सड़क नेटवर्क को सुगम और चौड़ा बनाया जा रहा है, ताकि यातायात व्यवस्था बेहतर रह सके और शहर में आवागमन बाधित न हो.

सिंहस्थ मेला अधिकारी और कलेक्टर पहुंचे-सिंहस्थ मेला अधिकारी, सह संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर रोशन सिंह ने चिंतामन गणेश मंदिर के समीप चिंतामन रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी के लिए बनाए जा रहे 12 मीटर चौड़े मार्ग निर्माण कार्य देखा, अधिकारियों ने मौके पर निर्माण कार्य की प्रगति की जानी. अफसरों ने बताया कि सिंहस्थ महापर्व के दौरान चिंतामन रेलवे स्टेशन तक पहुंचने वाला यह मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा. इस सड़क का निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा होगा.

गाड़ी अड्डा से वीडी क्लॉथ मार्केट-शहर में चल रहे प्रमुख मार्ग चौड़ीकरण कार्य भी चल रहे हैं, अधिकारियों ने गाड़ी अड्डा से वीडी क्लॉथ मार्केट और तेलीवाड़ा से ढाबा रोड तक लगभग 1.6 किलोमीटर लंबाई में किए जा रहे 15 मीटर चौड़ीकरण कार्य की चिंता भी पाली, साथ ही कोयला फाटक से नरेंद्र टाकीज तिराहा होते हुए कंठाल चौराहे तक लगभग 1.23 किलोमीटर लंबे मार्ग के 15 मीटर चौड़ीकरण कार्य का भी पैदल भ्रमण करते हुए यहां श्रद्धालुओं की सुविधा क्या-क्या बढ़ाई जा सकती है यह भी तय किया.

> **संसाधन बढ़ाकर व्यवस्थित ढंग से करें कार्य**
>
> निरीक्षण के दौरान निर्माण एजेंसियों से कार्य की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली और निर्देश दिए कि सभी प्रमुख मार्गों पर चौड़ीकरण का कार्य तेजी से किया जाए, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निर्माण कार्य के दौरान शहरवासियों को आवागमन में अनावश्यक परेशानी न हो. इसके लिए आवश्यक संसाधन बढ़ाकर कार्य को व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जाए.
>
> **आशीष सिंह, संभाग आयुक्त एवं सिंहस्थ मेला अधिकारी उज्जैन**

समग्र विकास का अवसर

सिंहस्थ महापर्व केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि उज्जैन के समग्र विकास का भी अवसर है. इस आयोजन के माध्यम से शहर की सड़कें, यातायात व्यवस्था और आधारभूत सुविधाएं बेहतर बनाई जा रही हैं, जिससे आने वाले वर्षों में भी शहरवासियों को इसका लाभ मिलेगा. प्रशासन का प्रयास है कि सिंहस्थ 2028 से पहले सभी प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण और निर्माण कार्य समय पर पूर्ण हो, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और उज्जैन शहर एक व्यवस्थित और सुगम धार्मिक नगरी के रूप में सामने आए.

- रोशन सिंह, कलेक्टर उज्जैन

गंभीर आरोप | कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा- किसानों के अधिकार और खाद्य सुरक्षा खतरे में

एमपी खाद्यान्न उपार्जन प्रणाली में 'लूट' : पटवारी

विशेष संवाददाता

भोपाल, 4 अप्रैल. जीतू पटवारी, मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ने राज्य की खाद्यान्न उपार्जन, भंडारण और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था में व्यापक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विफलता और राजनीतिक संरक्षण के गंभीर आरोप लगाते हुए इसे 'संगठित लूट' करार दिया है, जो किसानों के अधिकारों और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल रही है.

उन्होंने दावा किया कि रायसेन जिले के वेयरहाउसों में लगभग 20,000 मीट्रिक टन गेहूं, जिसे 35 करोड़ रुपये की लागत से खरीदा गया था, सड़ने के लिए छोड़ दिया गया. रखरखाव और कीटनाशक के नाम पर इसकी लागत 150 करोड़ रुपये तक पहुंचा दी गई. 34 बार छिड़काव के बावजूद अनाज के खराब हो जाने को उन्होंने फर्जी बिलिंग और अधिकारियों-ठेकेदारों की मिलीभगत का परिणाम बताया. पटवारी ने कहा कि यह समस्या व्यापक है.

35 करोड़ से खरीदा गया था 20,000 मीट्रिक टन गेहूं

4 वर्षों में प्रदेश में 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं सड़ चुका

पिछले चार वर्षों में प्रदेश में 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं सड़ चुका है, जिससे लगभग 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

जबलपुर और सिवनी में सामने आए 'घोस्ट ट्रांसपोर्ट' घोटाले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 92 प्रतिशत ट्रिप फर्जी थीं, जिनमें स्कूटर जैसे वाहनों से भारी मात्रा में अनाज ढोने का दावा किया गया.

> उन्होंने वेयरहाउस आवंटन में पक्षपात और भुगतान में अनियमितताओं का भी आरोप लगाया. 26 प्रतिशत से अधिक बच्चों में कुपोषण का हवाला देते हुए उन्होंने स्थिति को गंभीर बताया. कांग्रेस ने मामले की फोरेंसिक जांच, आवंटन में पारदर्शिता, दोषियों पर आपराधिक कार्रवाई, नुकसान की भरपाई और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सख्त गुणवत्ता नियंत्रण की मांग की है.

गेहूं खरीदी में देरी पर सरकार को घेरा

विशेष संवाददाता

भोपाल, 4 अप्रैल. पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी में हो रही लगातार देरी पर कड़ा विरोध जताते हुए इसे 'अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, किसान-विरोधी और असंवेदनशील' बताया है.

उन्होंने कहा कि किसान पहले ही प्राकृतिक अनिश्चितताओं, बढ़ती लागत, कर्ज के बोझ और बाजार की अस्थिरता से जूझ रहा है. ऐसे समय में खरीदी टालना किसानों के साथ अन्याय है. सिंह ने चिंता जताई कि किसान अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बेचने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी में उन्हें निजी व्यापारियों को कम दाम पर गेहूं बेचना पड़ रहा है. इससे किसानों को सीधा आर्थिक नुकसान हो रहा है और विशेष रूप से बैंक ऋण पर निर्भर किसान डिफॉल्ट की स्थिति में पहुंच रहे हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बारदाने की कमी का हवाला देकर खरीदी में देरी कर रही है, जबकि बाजार और व्यापारियों के पास पर्याप्त बारदाना उपलब्ध है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब व्यापारी बड़े स्तर पर खरीदी कर सकते हैं, तो सरकार एमएसपी पर खरीदी क्यों नहीं कर पा रही है.

> अजय सिंह ने यह भी कहा कि राजस्थान जैसे राज्यों में गेहूं खरीदी शुरू हो चुकी है, जबकि मध्य प्रदेश के किसान अब भी इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने तत्काल खरीदी शुरू करने, खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाने, बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था करने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो यह धारणा मजबूत होगी कि सरकार किसानों के बजाय व्यापारिक हितों को प्राथमिकता दे रही है.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60